622

किरपाल सिंह, एम. एल. ए. बनाम उत्तम सिंह और ए. एन. आर.

9 अक्टूबर, 1985

चिनाप्पा रेड्डी, ई. एस. वेंकटकामिया, वी. बालाक्रिष्णा एराडी, आर. बी. मिस्का और वी. खालिद, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के साथ पठित अनुच्छेद 191 (1) (ए)-सदस्यता के लिए अयोग्यता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रयोज्यता-निर्वाचित होने का अधिकार और लोगों के लिए बोलने का अधिकार संसद द्वारा तय किए जाने वाले प्रश्न हैं न कि अदालत द्वारा चुनाव अपील में पारित किए जाने वाले अंतरिम आदेशों की प्रकृति जब चुनाव को अधिनियम के भाग VII द्वारा कवर नहीं किए गए आधारों पर दरकिनार कर दिया गया था।

अपीलार्थी कृपाल सिंह 1972 में हुए आम चुनावों में मजीठा निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए थे। पराजित उम्मीदवारों में से एक द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। इस आधार पर कि किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस कारण से अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था कि वह जीवन के रोजगार में एक विकास अधिकारी था बीमा निगम जिसके कर्मचारी विनियमों के तहत वह था चुनाव की मांग करने से प्रतिबंधित। उच्च न्यायालय का विचार था कि कर्मचारियों के नियम, सबसे अच्छा, बसंत सिंह को बना सकते हैं केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी। धारा के तहत अपील में 116 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का ए, न्यायालय अपीलार्थी को उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया सभा में भाग लिए बिना रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें कार्यवाही या मतदान, और बिना कोई पारिश्रमिक लिए। अपील दायर करने के बाद, तीन आम चुनाव हुए जिसके परिणामस्वरूप अपील पूरी तरह से निष्फल हो गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय,

अभिनिर्धारित: 1.1 . जहाँ एक चुनाव को विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार की कोई गलती नहीं होने के कारण अलग रखा जाता है, जैसे कि एक भ्रष्ट प्रथा उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा या उसके द्वारा अनुभव की गई अयोग्यता, लेकिन इस आधार पर कि किसी और का नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, अधिक उपयुक्त अंतरिम आदेश शायद होगा पूर्ण स्थगन प्रदान करें ताकि निर्वाचन क्षेत्र न जाए निर्वाचित या उन लोगों की कोई गलती के लिए प्रतिनिधित्व नहीं किया गया जो चुने गए। [624 सी-डी]

1.2 ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा लागत का अधिनिर्णय अनुचित है। अपीलार्थी उसे प्राप्त करेगा। उस अवधि के लिए पारिश्रमिक जिसके लिए वे एक विधायक के रूप में चुने गए थे। [626 सी-डी] 1.3 अनुच्छेद 191 (1) (ए) से (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट

और निस्संदेह उद्देश्य अनुच्छेद 191 (1) (ए) को राज्य निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त विधान द्वारा विस्तारित किया जाना चाहिए, नीति का एक बेहतर प्रश्न है, जिसका निर्णय स्वयं जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, न कि उस न्यायालय के लिए जिसका निर्णय केवल व्याख्या तक ही सीमित हो सकता है। [625 ई-एच; 626 ए] (न्यायालय ने सरकार से विधि आयोग द्वारा उसके समक्ष रखे गए कई प्रश्नों की शीघ्र जांच करने की सिफारिश की।)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 650 (एन. सी. ई.) 1975 से। 14. 3 के निर्णय और आदेश से। 1975 1972 की निर्वाचन याचिका संख्या 27 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से। अपीलार्थी के लिए के. के. गर्ग, ए. के. गांगुली, एम. एम. क्षत्रिय और श्रीमती वंदना शर्मा। जी. एल. सांघी, पी. एच. पारेख और पी. के. मनोहर उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था चिनाप्पा रेड्डी, जे. श्री कृपाल सिंह पंजाब विधान सभा के लिए मजीठा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। 1972 में आम चुनाव हुए। हारने वाले उम्मीदवारों में से एक द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया था कि दूसरे उम्मीदवार के नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था। बसंत सिंह नामक एक व्यक्ति का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बसंत सिंह जीवन बीमा निगम में एक विकास अधिकारी थे और इसलिए जीवन बीमा निगम के कर्मचारी विनियमों के तहत विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि बसंत सिंह ने कर्मचारी विनियमों की अवहेलना की और विधानसभा के लिए चुनाव की मांग की तो उन्होंने खुद को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया होगा, लेकिन इससे उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधानसभा के लिए चुनाव की मांग से। इसलिए बसंत सिंह के नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया और कृपाल सिंह का चुनाव रद्द कर दिया गया। उनके चुनाव को रद्द कर दिए जाने के बाद उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व की धारा 116-ए के तहत इस अदालत में अपील की। एक्ट करें। अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया जिसमें अपीलार्थी को विधानसभा में भाग लेने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया गया। कार्यवाही या मतदान और बिना कोई पारिश्रमिक लिए। अंतरिम आदेश देने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति किसी भी तरह के अनादर के बिना हम सोचते हैं कि जहां चुनाव को किसी के लिए अलग रखा जाता है उसकी गलती, जैसे कि उसके या उसके द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथा अभिकर्ता या अयोग्यता उसे झेलनी पड़ी, लेकिन जमीनी स्तर पर कि किसी और का नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, अधिक उपयुक्त आदेश शायद एक पूर्ण रोक देना होगा। ताकि निर्वाचन क्षेत्र बिना किसी गलती के प्रतिनिधित्व के न जाए या तो निर्वाचित या जिन्होंने चुना।अपील दायर करने के बाद, वहाँ है तीन और आम चुनाव। वर्तमान अपील इस प्रकार बन गई है पूरी तरह से निष्फल, वास्तव में कानूनी प्रक्रिया पर एक दुखद टिप्पणी। यद्यपि उठाया गया प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उत्पन्न हो सकता है। भविष्य में बार-बार हम ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं इस पर घोषणा क्योंकि हम सोचते हैं कि मामला एक है जो संसद से विचार प्राप्त करना चाहिए और उपयुक्त कानून बनाया जाए। कला के

तहत। 191 (1) संविधान का ए व्यक्ति के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, और होने के लिए विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य राज्य -

(क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है,राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित नहीं अपने धारक को अयोग्य ठहराएँ;

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; किरपाल सिंह वी. उत्तम सिंह [चिनाप्पा रेड्डी, जे.] 625

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी निष्ठा की स्वीकृति के अधीन है या एक विदेशी राज्य का पालन;
(ङ) यदि वह बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है। संसद द्वारा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का अध्याय III जो निश्चित रूप से कला के अर्थ में संसद द्वारा बनाया गया कानून है।

191 (1) (ङ) संविधान में संसद और राज्य की सदस्यता के लिए अयोग्यता के कुछ और आधार बताए गए हैं। सभाएँ। विशेष रूप से हम धारा 10 का उल्लेख कर सकते हैं जो कहती है," सरकारी कंपनी के तहत पद के लिए अयोग्यता-एक व्यक्ति को तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी कंपनी या निगम (एक सहकारी समिति के अलावा) का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है। सरकार के पास बीस-पाँच प्रतिशत से कम नहीं है। साझा करें "। कला का स्पष्ट और निर्विवाद उद्देश्य। 191 (1) (क) से (ङ) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान (जिनमें शामिल हैं)

सेक. 10) सरकारी या राज्य कर्मचारियों को चुनाव में भाग लेने से रोककर चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता का संरक्षण करना है। लेकिन फिर सेक। 10 अयोग्यता को सीमित करने के लिए प्रतीत होता है, जहाँ तक यह कर्मचारियों से संबंधित है कला के तहत। 191 (1) (ई) ? या सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या उनमें से कुछ अवांछनीय दबाव डालने के लिए बेहतर स्थिति में नहीं हैं, सरकारी कर्मचारियों से? दूसरी ओर, क्या सार्वजनिक निगमों के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाने के अवसर से वंचित किया जाना चाहिए?

सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। क्या कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। क्या उच्च या मध्यम साक्षर लोगों के एक बड़े समूह को लोगों के लिए बोलने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए? क्या निर्वाचित होने का अधिकार, सीमित होने का अधिकार, जिसका कोई मतलब नहीं है, केवल पेशेवर राजनेताओं के प्रति कोई अनादर है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिनके उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। इसका सबसे अच्छा जवाब जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही दिया जाना चाहिए। हम इन प्रश्नों के निर्णय से पीछे नहीं हट रहे

हैं, लेकिन हमारा निर्णय केवल व्याख्या तक ही सीमित हो सकता है। ऐसा नहीं है, संसद जो इस पर निर्णय ले सकती है नीति। इसलिए, हम सरकार से विधि आयोग द्वारा इस मामले की जल्द से जल्द जांच करने की सिफारिश करते हैं। भविष्य में जब कोई उपयुक्त अवसर आएगा तो हम निश्चित रूप से इस मामले से निपटेंगे, शायद नए कानून से मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ जुर्माना लगाया है। कि अनावश्यक था। हम आदेश के उस हिस्से को अलग रखते हैं। हम व्यक्त करते हैं अन्य प्रश्नों पर कोई राय नहीं। अपीलार्थी उसे प्राप्त करेगा। उस अवधि के लिए विधायक के रूप में वह पारिश्रमिक था।